State agricultural Universities including National Research Institutes, National Research Centres, Project Directorate of different Crops etc. The varieties and technologies so developed are tested at diverse agro-climatic condition before recommending for adoption under specific location. Andhra Pradesh is also covered under these Coordinated Programmes.

(d) and (e) A sum of Rs. 1746.71 lakhs was allocated under AICRP and National Research Centres in Andhra Pradesh during 1997-98.

**Outlay on Agricultural Research**

2494. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the outlay on agriculture research instead of depending on foreign firms;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the measures initiated to protect the farmers already affected by the multinational companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The Department does not depend on any foreign firm to increase the outlay on agricultural research. However, the Department has proposed to the Planning Commission and Ministry of Finance for increase in the outlay on agricultural research to the tune of 1% of Agricultural Gross Domestic Product. Presently, the Department is investing about 0.6% of Agricultural GDP on agricultural research.

(c) The question does not arise.

**उर्वरकों की खरीद में कमी**

2495. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि से किसानों द्वारा उर्वरकों की खरीद में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव रबी की फसल पर नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो निचले और मध्यम वर्ग के किसानों को उर्वरकों खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल):** (क) और (ख) यूरिया का मूल्य 29.1.99 से 340 रु० प्रति मीटरी टन बढ़ा दिया गया था। किसी माह विशेष में उर्वरकों की बिक्री इसके मूल्य सहित बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। हालांकि फरवरी, 1999 के दौरान यूरिया की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, फिर भी फरवरी, 1999 के अंत तक रबी की कुल बिक्री 85.97 लाख मी० टन० थी। जबकि पिछले रबी की इसी अवधि के दौरान 83.24 लाख मी० टन थी। अत: यूरिया के मूल्य में वृद्धि से मौजूदा रबी फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ग) यूरिया के मूल्य में हाल की वृद्धि के पश्चात् भी यूरिया तथा फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर सभी वर्गों के किसानों के लिये अत्यधिक राजसहायता दी जा रही है।

**प्याज का प्रत्याशित उत्पादन**

2496. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों से प्याज की नई फसल खरीदने का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 1999 के दौरान राज्य-वार का अनुमानत: कुल कितना उत्पादन होगा;

(ग) क्या गत वर्ष के प्याज संकट को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 1999 के लिए घरेलू खपत हेतु प्याज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्याज के निर्यात के पुन: आदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल):** (क) सरकार को मंडी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत प्याज की खरीद के लिए किसी भी राज्य से प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान प्याज के प्रत्याशित राज्य वार उत्पादन का विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**)।

(ग) भारत सरकार की प्याज के भण्डारण की कोई स्कीम नहीं है।

(घ) और (ङ) प्याज के निर्यात पर लगी रोक पहली फरवरी, 1999 के आंशिक रूप से हटा ली गई थी और बंगलौर के रोज़ प्याज तथा कृष्णापुरम् प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई। दोनों सरकारों द्वारा श्रीलंका को 3000 मी. टन प्याज के निर्यात की पारस्परिक अनुमति